बिहार पशु चिकित्सा संघ

कार्यालय - विद्यापति मार्ग, पटना-800001

डॉ० विनोद कुमार मुक्ता

प्रधान महासचिव

मो० 7488601083

e-Mail : bvapatna@gmail.com

पत्रांक- 43 दिनांक- 10.05.2020

सेवा में,

प्रधान सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः— **प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर भ्रमणशील पशुचिकित्सा पदाधिकारी / प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी को दंडाधिकारी / गैर विभागीय कार्य में ड्यूटी लगाने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर निवेदन पूर्वक कहना है राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में सभी सरकारी पशुचिकित्सालय एवं कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खुले रहेंगे, जहाँ प्रतिदिन पशु चिकित्सा पदाधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य है। इस जानकारी के बावजुद विभिन्न प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा भ्रमणशील पशुचिकित्सा पदाधिकारी / प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी की ड्यूटी COVID – 19 Quarantine Centre या अन्य कार्यो में लगा दी गई है (छायाप्रति संलग्न), जिससे पशुचिकित्सालयों को बंद करने की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसा सिर्फ वर्त्तमान परिस्थिति में ही नहीं है, बल्कि पूर्व में भी समय–समय पर इन अधिकारियों की ड्यूटी प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा दंडाधिकारी / गैर विभागीय कार्य में लगा दी जाती है (छायाप्रति संलग्न), जो कि राज्य सरकार के आदेश (छायाप्रति संलग्न) और माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश (छायाप्रति संलग्न) का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः महोदय से सादर अनुरोध है कि इस संबंध में भविष्य में किसी भी भ्रमणशील पशुचिकित्सा पदाधिकारी / प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी की ड्यूटी प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा किसी प्रकार के दंडाधिकारी / गैर विभागीय कार्य में नहीं लगाये जाने संबंधी स्पष्ट आदेश निर्गत करने की महती कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक :- यथोक्त

(डा0 विनोद कुमार मुक्ता)
प्रधान महासचिव

/

प्रखंड कार्यालय, रूपौली।

—: आदेश :—

जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के आदेश ज्ञापांक 1340/पूर्णियाँ (Quarantine Cell), दिनांक 03.05.2020 द्वारा प्रखंड स्तर पर COVID-19 कोरोना संक्रमण के दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों की आने की संभावना को देखते हुए उनके आवागमन के पश्चात अगले 21(इक्कीस) दिनों तक प्रथम चरण के तहत् प्रखंड मुख्यालय अवस्थित चिन्हित Quarantine भवनों में आवासन की समुचित व्यवस्था करने हेतु निदेशित किया गया है।

अतएव जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा दिये गये आदेश के आलोक में COVID-19 कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित कोषांग का गठन किया जाता है।

आवासन कोषांग का दायित्व

इस कोषांग के सफल संचालन हेतु डॉ मनमोहन कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सक, रूपौली (मो0–829887456, 79797758814) को नोडल पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। इन्हें निम्न दायित्व सौंपा जाता है।

1. प्रत्येक आवासन भवन में कम से कम छः फीट की दूरी पर कॉट (Cot) बिछावन, बेडसीट, तकिया एवं मच्छरदानी की व्यवस्था करना।
2. महिला एवं पुरूष के लिए 20 से 25 की संख्या पर अलग–अलग शौचालय तथा स्नाानागार की व्यवस्था कार्यपालक अभियंता PHED से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराना। ऐसे शौचालयों को नम्बरिंग कर उसके व्यवहार में लाने वाले व्यक्तियों को सूचीबद्ध करना।
3. प्रत्येक आवासन भवन में पर्याप्त प्रकाश तथा मोबाईल चार्ज हेतु बोर्ड की व्यवस्था करना।
4. प्रत्येक भवन को CCTV Camera से आच्छादित करना जो प्रखंड मुख्यालय से जुड़ा रहेगा।
5. प्रत्येक व्यक्ति को अलग–अलग भोजन के लिए थाली, ग्लास एवं कटोरी तथा एक–एक प्लास्टिक की बाल्टी एवं मग उपलब्ध कराना।
6. शौचालय के लिए हैंडवास (Handwash) उपलब्ध कराना।
7. शौचालय के निकट प्रकाश की व्यवस्था करना।
8. प्रत्येक पुरूष को धोती/लुंगी, गमछा जबकि महिलाओं को साड़ी तथा छोटे लड़के के लिए पैंट शर्ट तथा लड़कियों को फ्रॉक तथा सभी को अलग–अलग कंघी, आईना, ब्रश, पेस्ट, Sanitizer, साबुन(नहाने एवं कपड़ा धोने के लिए) मुहैया कराना। उपलब्ध कराये गये ये सभी सामग्री Quarantine अवधि समाप्त होने के बाद अपने साथ ले जा सकेंगे।
9. ठहरे हुए प्रत्येक व्यक्ति का Skill Mapping कराना ताकि उनकी दक्षता के अनुरूप स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराया जा सके।

भोजन कोषांग का दायित्व

इस कोषांग के सफल संचालन हेतु डॉ राकेश कुमार रौशन, भ्रमणशील पशु चिकित्सक, रूपौली (मो0–8757171047, 7903104548) को नोडल पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। इन्हें निम्न दायित्व सौंपा जाता है।

1. आवासन भवन (Quarantine) में ठहरने वाले व्यक्तियों के लिए सुबह में आठ बजे चाय, दिन में 12.00 बजे मध्याह्न में भोजन एवं रात्रि में 8.00 बजे शाकाहारी भोजन तथा उन्हें दोनों वक्त Milk Powder से तैयार एक–एक ग्लास दूध उपलब्ध कराना है।

Scanned by CamScanner

2. इन Quarantine सेन्टर से निकलने वाले जूठे प्लेट एवं ग्लास को एकत्रित करने हेतु पर्याप्त संख्या में डस्टबीन रख कर उसकी नियमित सफाई कराना।
3. खिलाने हेतु सोशल डिस्टेसिंग का ध्यान रखते हुए Shift Wise व्यवस्था करना। खिलाने के पहले फर्श की लाइजोल से अच्छी तरह सफाई करा लेना आवश्यक होगा।
4. खाना खिलाने वाले व्यक्ति को चिन्हित करने हेतु Apron के साथ–साथ उन्हें हेंड कवर, मास्क, Gloves आदि उपलब्ध कराना।
5. इस दौरान यह भी ध्यान रखना होगा कि भोजन देते वक्त उचित बर्त्तन (बड़ा चम्मच/कलछूल आदि) का प्रयोग किया जाए।
6. ऐसी व्यवस्था करना है कि आवासित (Quarantine सेन्टर में रहने वाले) व्यक्तियों को गर्म खाना ही खिलाया जाए।
7. खाना बनाने वाला एवं खिलाने वाले व्यक्ति प्रतिदिन सुबह में न सिर्फ साबुन से स्नान करें बल्कि उनके कपड़े भी धूले हुए साफ होने चाहिए।
8. खाना बनाने वाले एवं आवासन की व्यवस्था में लगे प्रत्येक कर्मी को हेड कवर (Head Cover) मास्क एवं Sanitizer के तौर पर साबुन उपलब्ध कराना ताकि वे उसका नियमित उपयोग कर सके।
9. बजार से लाए गए हरी सब्जियों को उपयोग में लाने के पूर्व गर्म पानी से अच्छी तरह से धुलवाना।
10. किसी भी परिस्थिति में बासी यानि घंटों पूर्व बने भोजन का वितरण वर्जित होगा।

House Keeping कोषांग का दायित्व

इस कोषांग के सफल संचालन हेतु श्री सुभाष कुमार, कनीय अभियंता, रूपौली (मो0–887739212981) को नोडल पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। इन्हें निम्न दायित्व सौंपा जाता है।

1. महिलाओं एवं पुरूषों के लिए प्रखंड में अलग–अलग Quarantine Centre स्थापित करना।
2. प्रत्येक Block Quarantine Centre में ठहरे हुए व्यक्तियों की समुचित जानकारी निम्नांकित प्रपत्र में पंजी के माध्यम से सूचीबद्ध करना।

आपदा राहत	फ्लैक्स का नमूना
प्रखण्ड Quarantine Centre	
प्रखण्ड का नाम	जिला–पूर्णियॉं
प्रखण्ड क्वॉरंटीन सेन्टर (Block Quarantine Centre)	
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का मोबाईल नं0	
अंचल अधिकारी का मोबाईल नं0	
थानाध्यक्ष का मोबाईल नं0	
चिकित्सा पदाधिकारी को मोबाईल नं0	
जिला नियंत्रण कक्ष, पूर्णियाँ का नम्बर	

3. Quarantine Centre में ठहरे हुए व्यक्तियों की सूची Mobile No. सहित Quarantine Centre भवन के सामने भाग में चस्पा करना ताकि बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्तियों को बिना भवन के अन्दर गये आवश्यक जानकारी उपलब्ध हो सके।

Scanned by CamScanner

4. इस कोषांग के प्रभारी की यह जिम्मेवारी होगी कि Quarantine किए गए व्यक्तियों के मोबाईल को रिचार्ज कराने में आवश्यक सहयोग प्रदान करें ताकि उन्हें किसी भी परिस्थिति में संटर से बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े।
5. प्रत्येक Block Quarantine भवनों के कमरों में टी0भी0 एवं केबल कनेक्शन के साथ–साथ आवश्यकतानुसार पंखों की भी व्यवस्था करना।
6. प्रखण्ड मुख्यालय के एक स्थान पर अवस्थित Quarantine Centre के लिए विद्युत के वैकल्पिक व्यवस्था यानि रात में बिजली कट जाने के उपरान्त समुचित प्रकाश हेतु जेनसेट/जेनेटर की व्यवस्था करना।
7. प्रत्येक सेन्टर पर एक आगन्तुक पंजी (Visitor Register) का निम्नांकित प्रपत्र में संधारण करना होगा।

क्रमांक	Block Quarantine Centre का नाम	निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी का पदनाम	निरीक्षण की तिथि	समय	निरीक्षण टिप्पणी

8. इस कोषांग का दायित्व होगा कि Block Quarantine Centre में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को निम्नांकित प्रपत्र में सूचीबद्ध करें।

क्रमांक	Quarantine Centre में ठहरे व्यक्ति का नाम	पिता/पति का नाम	उम्र	पता	मोबाईल नं0	सेन्टर में आने की तिथि	किस राज्य से आए हैं।	क्या उनमें कोरोना के आरम्भिक लक्षण है अथवा नहीं।	अभ्युक्ति

ज्ञापांक 1662 / दिनांक 06/05/2020

प्रतिलिपिः– सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– अंचलाधिकारी, रूपौली को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी, धमदाहा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– उप विकास आयुक्त, पूर्णियाँ को सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रखंड विकास पदाधिकारी
रूपौली

Scanned by CamScanner

प्रखंड कार्यालय सोनो

पत्रांक– 630 दिनांक– 8-09-18

प्रेषक,

प्रखंड विकास पदाधिकारी,
–सह–
प्रखंड स्वच्छता पदाधिकारी,
सोनो।

सेवा में,

श्री कृष्णा सिंह, पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक ,सोनो।

श्री सुबोध कु0 सक्सेना, भ्रमनशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, सोनो।

विषय– पैरामटिहाना , बाबुडीह पंचाय के नोडल प्रतियुक्त करने के संबंध में।

महाशय ,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है। कि प्रखंड सोनो के अंतर्गत प्रशासनिक दृष्टिकोण से निम्न पंचायतों के नोडल पदाधिकारी स्वच्छता से संबंधित कार्य करेंगे।

क्र0सं0	पंचायत का नाम	प्रभारी नोडल पदा0 के नाम	पदनाम	[illegible]0 नं0
1.	पैरामटिहाना	श्री सुबोध कु0 सक्सेना	भ्रमनशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी	9631631920
2.	बाबुडीह	श्री कृष्णा सिंह	पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक	9955803476

तत्काल प्रभाव से यह आदेश लागू होगा।

विश्वासभाजन

[signature] 8.9.18

प्रखंड विकास पदाधिकारी
–सह–
प्रखंड स्वच्छता पदाधिकारी,
सोनो

Scanned with CamScanner

पत्रांक–बी/विविध(दण्डाधिकारी की शक्ति)–22/2016 ..../

बिहार सरकार

गृह विभाग

प्रेषक,

पारस नाथ
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार

पटना, दिनांक– 2019

विषयः– विधि–व्यवस्था संधारण हेतु दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करने के संबंध में।

महाशय,

राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता विधि–व्यवस्था सुदृढ़ करते हुए कानून का शासन स्थापित कर लोगों को भयमुक्त समाज प्रदान करने के साथ–साथ चहुँमुखी विकास की रही है। विगत कुछ वर्षों में पर्व–त्यौहारों के अवसर पर और विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने पर विधि–व्यवस्था संधारण करने हेतु बिहार प्रशासनिक सेवा, राजस्व सेवा और ग्रामीण विकास सेवा के पदाधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के अभियंताओं, पदाधिकारियों को दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता रहा है। विभिन्न तकनीकी अथवा विकासात्मक विभागों के अधिकांश कनीय पर्यवेक्षी पदाधिकारी की पर्याप्त वरीयता एवं प्रशिक्षण के अभाव में कार्यकुशलता की कमी के साथ–साथ विभागीय कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है और उनकी दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति प्रभावकारी नहीं रही है।

सम्यक विचारोपरान्त दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित निदेश दिए जाते हैं :–

1. अतिसंवेदनशील स्थानों पर अपर जिला दण्डाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडलों में पदस्थापित कार्यपालक दण्डाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/बि.प्र.से. के अन्य पदाधिकारी को ही दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति किया जाए।

2. अन्य स्थानों पर पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति किया जाए।

3. बिहार प्रशासनिक सेवा के अतिरिक्त अन्य दोनों सेवाओं के जिन पदाधिकारियों को दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाना हो, वैसे पदाधिकारियों की सूची तैयार किया जाए और उन्हें दंडाधिकारी के कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों और शक्तियों के बारे में अनिवार्य रूप से प्रशिक्षित किया जाए। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम BIPARD में आयोजित किया जाएगा।

OSD / both SDO / all BDOs

विश्वासभाजन

ह0/–
(पारस नाथ)
सरकार के विशेष सचिव

457
27-6-19

10sDo/M/Sankalp

ज्ञापांक :– ..../ पटना, दिनांक ,2019

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक :– ..../ पटना, दिनांक ,2019

प्रतिलिपि :– सभी प्रमण्डीय आयुक्त/पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक (विधि–व्यवस्था)/सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/सभी क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक :– ..../ पटना, दिनांक ,2019

प्रतिलिपि :– महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, वाल्मी परिसर, फुलवारी शरीफ, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक :– ..../ पटना, दिनांक ,2019

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 6618/ पटना, दिनांक 24/6/2019

प्रतिलिपि :– आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को Website पर Upload करने हेतु प्रेषित।

24.6.19
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक 1865/गो० दिनांक 27.6.2019

प्रतिलिपि :– सभी अनुमण्डल पदा० /सभी प्रखण्ड विकास पदा०, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदा०
जिला गोपनीय शाखा,
बक्सर।
27/6/19

11-D:/M-Sankalp

Patna High Court
Dr. Ajay Kumar vs The State Of Bihar And Ors. on 3 January, 2007
Equivalent citations: 2007 (1) BLJR 599
Author: S Hussain
Bench: S Hussain
ORDER S.N. Hussain, J.

Page 0600

1. Heard learned Counsel appearing for the petitioner and learned Counsel appearing for the State.

2. This writ petition has been filed for quashing that part of the Government Notification bearing No. 5 M(3) 104/85-P, Pa. 4329 dated 1.5.1985 (Annexure-3) by which the services of the Block Animal Husbandry Officers have been placed under the Rural Re-Construction and Panchayati Raj Department and the Block Development Officer has been made local controlling authority of the Block Animal Husbandry Officers. It is further prayed that respondents authorities be restrained from utilising the services of the petitioner for any purpose other than those enumerated in the said notification dated 1.5.1985 specially when they do not form part of the regular duty to be performed by a Block Animal Husbandry Officer as envisaged in the said notification.

3. Learned Counsel for the petitioner submitted that the petitioner is a Veterinary Doctor having passed the Bachelor of Science and Animal Husbandry examination from Rajendra Agricultural University, Pusa in the year 1996 obtaining 1st Class, whereafter, he was appointed in the Bihar Veterinary Service Class II post in the year 1997 after completion of all the legal formalities. It is further submitted that at the time of filing of this writ petition the petitioner was working on the post of Block Animal Husbandry and Fisheries Officer, Government of Bihar, Patna and was working at Motihari in the District of West Champaran and was also doing post graduation from the Bihar Veterinary College, Patna which he subsequently completed in the year 2000.

4. Learned Counsel for the petitioner relied upon a decision of this Court dated 20.05.1997 (annexure-5) passed in CWJC No. 12146 of 1996 (Bihar Veterinary Association through its General Secretary and Ors. v. The State of Bihar and Ors.) by which the respondents were directed to give similar treatment to the petitioners of that writ petition in the matter of revised pay scale pursuant to the recommendation of 5th Pay Revision Committee with effect from 1.1.1986 on the basic grade Page 0601 scale of pay of Rs. 2200-4000/-. Thereafter, the said order was implemented by the State Government by memo No. 3M-5-5-70/94 Vi 31/95 dated 27.09.1997 (annexure-6). Hence, learned Counsel for the petitioner submitted that the Block Animal Husbandry Officers were also held to be Class II employees and, therefore, they cannot be placed under the control, supervision and authority of the Block Development Officer who is of the same rank.

5. Learned Counsel for the petitioner also submitted that subsequently, in the case of Bihar Veterinary Association and Ors. v. The State of Bihar and Ors. reported in 2005 (3) P.L.J.R 430 it has been held that the recommendation of the Fitment Committee was wrong and it should have recommended the pay scale of Rs. 8,000/-- 13,500/- for the basic grade of the Bihar Animal

Husbandry Services and accordingly the resolution of the State Government dated 08.02.1999 was modified to that extent as recommended by the Committee for the basic grade scale of Rs. 6500-10,500/-. In the circumstances, learned Counsel for the petitioner stated that the said scale being Class I grade scale the Animal Husbandry Officers were held to be Class I Officers and as such the notification of the State Government was, more so, not justified as the Block Development Officers continue to be Class II Officers.

6. Learned Counsel for the petitioner further submitted that the Bihar Animal Husbandry Officers cannot be legally deputed for non-departmental work and they have to be restricted to the job for which they have been appointed. In this connection, he has relied upon a decision of this Court dated 22.10.2002 in CWJC No. 10132 of 2002 (Dr. Akhilesh Kumar Singh v. The State of Bihar and Ors.). He has also drawn attention of this Court to a circular of the State Government bearing Memo No. 15495 dated 16.12.1976 (Annexure-11) in which it was directed that only in emergent situations the Officers of the Animal Husbandry Department can be asked to perform duties other than the duties of their department.

7. On the other hand, learned Counsel for the respondents vehemently opposed the contentions of the learned Counsel for the petitioner and submitted that this writ petition has become infructuous as the petitioner has been transferred from the post and he is now not under any Class II Officer as he is presently working as Junior Research Officer in the Institute at Patna. He further stated that the amendment of the Constitution of India in the year 1993 regarding Panchayat Raj has not been considered in the earlier decisions of this Court and hence, after the said amendments the situation has changed. He also averred that according to Section 61(b) and (c) of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006, the Executive Officer shall lay down the duties, supervise and control the officers including the Bihar Animal Husbandry Officers and Staff holding office under the Panchayat Samiti enacted in consonance with Articles 243, 243A to 243-O of the Constitution of India. He submitted that after the 73rd amendment of the Constitution and after enactment of Bihar Panchayat Raj Act, 1993, the Government of Bihar made a resolution about the functions of the Animal Husbandry Department under the management of Panchayat Raj vide resolution No. 5M(i) 304/201/P.Pa 5697 dated 25.9.2001 (Annexure-B to the counter affidavit). He also stated that the Block Development Officer is the Executive Officer of the Panchayat Samiti and he has been given power under the Bihar Panchayat Raj Act after the 73rd amendment of the Constitution to control the officers including the Block Animal Husbandry Officer.

Page 0602

8. In view of the aforesaid fact's, learned Counsel for the State averred that the impugned notification is legal and justified and neither there is any occasion to quash the said notification of the Government dated 1.5.1985 nor there is any reason for restraining the respondents authorities from utilising the services of the Block Animal Husbandry Officers for any work other than the duties in their department.

9. After hearing the learned Counsel for the parties and after perusing the materials on record, it is quite apparent that facts are not disputed in the instant case and the matter revolves around a few

decisions of this Court and the provisions of the Constitution of India and Bihar Panchayat Raj Act and its interpretation as well as certain Notifications/ Circulars of the State Government.

10. Learned Counsel for the petitioner has raised a preliminary objection that although the petitioner was, at the time of filing of the writ petition, posted as Block Animal Husbandry Officer with the Block Development Officer as his controlling authority, but he has been transferred from that post and is not now under any Class II Officer as he is presently working as Junior Research Officer in the Institute at Patna. There is neither any averment in the counter affidavit of the respondents, nor any submission has been made by their learned Counsel that in future also the petitioner will not be transferred and posted as Block Animal Husbandry Officer anywhere. In the said circumstances, there is no question of this writ petition becoming infructuous and the points in question have to be decided.

11. With respect to the question as to whether the Block Animal Husbandry Officers were Class II employees of the State Government, this Court has already decided the matter in CWJC No. 12146 of 1996 (Bihar Veterinary Association v. the State of Bihar and Ors.) vide order dated 20.5.1997 in which it has been held as follows:

In sum and substance the case of the petitioners is that they are members of Class II service in the Animal Husbandry Department and they are entitled to the aforesaid scales of pay and that they stand exactly on the same footing as the petitioners of CWJC No. 2537 of 1990.

My attention was drawn to the notification dated 11.7.1996 contained in Annexure-5 giving the benefit of the revised scales of pay as indicated hereinabove to the writ petitioners of CWJC No. 2537 of 1990 subject to the result of the LPA and the contempt petition. It was suggested that similar order may be passed in this case. In view of the fact that LPA has since been dismissed, I do not think any order is required to be passed in terms indicated in the aforesaid notification dated 11.7.1996. It is not in dispute that the petitioners stand on same footing as the petitioners of CWJC No. 2537 of 1990. In that view of the matter I would direct the respondents to give similar treatment to these petitioners in the matter of revised pay scale pursuant to the recommendation of the Fifth Pay Revision Committee with effect from 1.1.1986. An appropriate notification to this effect should be issued as early as possible preferably within a period of two months from the date of receipt/production of a copy of this order.

This writ petition stands disposed of accordingly.

This aspect of the matter cannot be and has not been disputed by the respondents in view of the well discussed judgment of this Court mentioned above. The said Page 0603 order of this Court was also implemented by the State Government vide memo No. 27.09.1997 (annexure-6). In the said circumstances, the Block Animal Husbandry Officers were clearly Class II employees of the Government and hence they could not have been legally placed under the control, supervision and authority of the Block Development Officers who are admittedly of the same rank, namely Class II.

12. In addition to the aforesaid averments, learned Counsel for the petitioner has also relied upon another decision of this Court in case of Bihar Veterinary Association and Ors. v. The State of Bihar and Ors., reported in 2005 PLJR 430 in which it has been held as follows:

28. The stand of the State Respondents that this writ application should be dismissed in the light of the orders of this Court dated 8.8.2002, passed in CWJC No. 8741 of 2002 whereunder similar prayer of the Deputy Collectors who belong to the Bihar Administrative Service has been rejected, shall also not persuade this Court to dismiss the present writ application as from the reasons indicated in paragraphs above, it would appear that the Bihar Animal Husbandry Service cannot be compared with the Bihar Administrative Service. The case law relied upon by the State Counsel has no applications to the facts of this case as in view of the terms of reference contained in Resolution dated 2.1.1998, Annexure-2, the Fitment Committee was under legal obligation to recommend exactly the similar scale which was recommended in the 5th Pay Revision Report to the counter part of the State Service.

29. In view of the discussions above, this Court concludes that the Fitment Committee should have recommended the scale of Rs. 8,000-13,500/- for the basic/entry grade of the Bihar Animal Husbandry Service and the Resolution of the State Government dated 8.2.1999, Annexure-4 is modified to that extent. The prayer of the petitioners to grant the scale of Rs. 10,000-15,200, 12,000-16,500 to those serving in Junior/ Senior selection grade of the basic/ entry grade of the Bihar Animal Husbandry Service, however, cannot be allowed as after adoption of the service conditions admissible to the Central Government employees the provision for grant of junior/senior selection grade stood abolished with effect from 1.1.1996 and the members of the Bihar Animal Husbandry Service serving in the junior/senior selection grade of the basic/entry grade until 31.12.1995 should also be fitted/adjusted in the scale of Rs. 8,000-13,500/- after granting them pay protection in the light of the stipulations made in paragraph 11 of the Resolution dated 8.2.1999, Annexure-4.

30. In the result, this application is allowed to the extent indicated above. No cost.

The law is thus well settled that the scale of Bihar Animal Husbandry Officer should be Rs. 8,000/- - 13,500/- for the basic grade and accordingly the resolution of the State Government was modified. Thus, the said scale being Class I grade scale, Animal Husbandry Officers were clearly held, to be Class I officers. In this view of the matter, the respondents authorities would be more so not justified in placing the services of Block Animal Husbandry officers under the control, supervision and authority of the Block Development Officers who are still Class II employees of the State Government.

13. So far the reliance of respondents counsel upon the provisions of the Bihar Panchayat Raj Act as well as the Constitution of India is concerned, the only two provisions of Section 61, namely Sub-sections (b) and (c), have been referred which Page 0604 only lay down the duty of supervision and control of the officers and staff holding the office under the Panchayat Samiti and execution of the works of the Panchayat Samiti. Articles 243 and 243 A to 243 O of the Constitution of India (as per 73rd amendment) relied upon by the learned Counsel for the respondents also do not speak with

respect to the instant matter.

14. Thus, the only material left for the respondents' to rely upon remains a resolution No. 5697 of the Animal Husbandry and Fisheries Department, Govt. of Bihar, dated 25th September, 2001 (annexure-B) in Clause 2 of which it has been mentioned that on the approval of the Pramukh of Panchayat Samiti, causal leave and permission for leaving the Headquarters could be given by the Block Development Officers to the Block Animal Husbandry Officers and Touring Animal Veterinary Officers. This is merely a circular of the Government which had been issued on the basis of the provisions of Bihar Panchayat Raj Act of 1993. Now the said Act has been repealed and new Panchayat Raj Act, 2006 has come into force and hence the Circulars or notifications issued under the previous Act cannot have any force of law specifically when the same is clearly in the teeth of the two decisions of this Court, both in case of Bihar Veterinary Association (supra) mentioned above.

15. So far the other question with respect to utilising the services of Block Animal Husbandry Officers for any work other than the duties in their department is concerned, learned Counsel for the petitioner relied upon a decision of this Court dated 22.10.2002 passed in CWJC No. 10132 of 2002 (Dr. Akhilesh Kumar Singh v. State of Bihar and Ors.) in which it has been held as follows:

The petitioner is a Touring Veterinary Officer presently posted at Goraul in Vaishali district. According to him in terms of the judgment of this Court in the case of Dr. Jagdish Prasad (CWJC No. 10040/04) disposed of on 20.4.1995 he cannot be asked to perform any duty which is not connected with his duties and functions as Touring Veterinary Officer and therefore issuance of show cause notice and stoppage of salary is without jurisdiction.

In the above said case of Dr. Jagdish Prasad, Block Animal Husbandry officer, the Deputy Commissioner, Sahebganj had issued an order deputing him as Magistrate in connection with law and order duty. He represented his case seeking exemption on the ground that he cannot be deputed to a non-departmental work. The Deputy Commissioner did not accept his plea and directed the Treasury Officer to withhold salary to him. The action of the Deputy Commissioner was held to be invalid in the eye of law and the Treasury Officer was directed to pass pending salary bills. In the facts of the case, the Deputy Commissioner was asked to pay cost for forcing the concerned petitioner to an avoidable litigation.

I find that the case of the petitioner is covered by the above said decision of this Court. It would accordingly follow that any direction by the District Magistrate asking him to perform duties which are not connected with his duties as Touring Veterinary Officer would be without jurisdiction. In the above view of the matter, the Treasury Officer, Hajipur is directed to clear the pending salary bills etc. of the petitioner according to rules.

The petition stands disposed of.

The decision of this Court in this regard is, thus, clear and the learned Counsel, for the respondents could not produce any material to show that either the law Page 0605 is different or any other view has been taken by any higher court in this regard. Hence, it is apparent that the authorities

concerned cannot legally ask the Block Animal Husbandry Officers to perform duties which are not connected with their duties in the department and any contrary direction given by the authorities concerned would be without jurisdiction.

16. In view of the aforesaid discussions, this writ petition is allowed and the impugned notification dated 01.05.1985 (annexure-3) is hereby quashed and the respondents-authorities are directed not to place the services of the petitioner under controlling authority of any Class II officer including Block Development Officer. The authorities are also restrained from utilising the services of the petitioner for any duty which is not connected with his duties in the department as Block Animal Husbandry Officer, if he is transferred or posted on that post.